The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b). No assessment as such has been made of the effects of the devaluation of the rupee on the Indian economy. Economic situation in the country is, however, kept constantly under review. The Economic Survey 1966-67, which has already been laid on the Table of the House, contains the latest review of the economy. A number of forces operate simultaneously in the economy and it is difficult to isolate the effects of devaluation alone. Export performance depends on the availability of surplus for exports which was adversely affected by the drought. World conditions of demand have also not been favourable on the whole and foreign prices of some of our exports have fallen. Debt service payments have also been rising. The internal price situation was affected, among other things, by adverse agricultural season.

(c) and (d). In order to strengthen the Rupee, the economy has to be strengthened and the productivity of the economy augmented. It is Government's constant endeavour to attain these objectives through all available and feasible instruments of policy.

आयकर अधिकारियों द्वारा आयकर का निर्धारण

230. श्री रवि राय :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री मधु लिमये :
श्री एस० एम० जोशी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कभी ऐसी शिकायतें मिली हैं कि आयकर अधिकारी अनेक ऐसे लोगों को जिनकी आय पर आयकर नहीं लगना चाहिये, सभी वर्षों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण पेश करने को कहते हैं ताकि उनके द्वारा निपटाये गये मामलों की संख्या बढ़ जाये और मामलों का उनका मासिक कोटा पूरा हो जाये;

(ख) क्या यह सच है कि आयकर अधिकारियों की कार्यकुशलता उनके द्वारा निपटाये गये मामलों की संख्या के आधार पर आंकी जाती है तथा निर्धारण पांच श्रेणियों में वर्गीकृत है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने आयकर विभाग में ऐसे मापदन्डों को बदलने के लिये कोई कदम उठाये हैं जिन से अवास्तविक कार्य-भार बढ़ता है और धोखा देने का अवसर मिलता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं ।

(ख) आयकर अधिकारी की कार्य-कुशलता का निर्णय कई बातों के आधार पर किया जाता है; कार्य की मात्रा उनमें से केवल एक है । मुख्य कसौटी तो कार्य के गुण की है जैसे कर की चोरी का पता लगाना और सही निर्धारण कर करना ।

कार्य की मात्रा के मूल्यांकन के निमित्त कर-निर्धारण के मामलों को पांच वर्गों में रखा गया है जो मुख्यतः आय की राशि पर आधारित हैं । ऐसा करने का कारण यह है कि आय की बड़ी रकम वाले मामले में कम आय के मामलों के मुकाबले अधिक समय लगता है ।

(ग) आयकर अधिकारियों के लिए काम के निर्धारित मानदण्डों की समीक्षा समय समय पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा आयकर आयुक्तों से परामर्श करके की जाती है । एक अधिकारी वर्ष भर में कितना काम कर सकता है, इसका वास्तविक अनुमान लगाकर ही मानदण्ड निर्धारित किया जाता है ।